19 मार्च 2026
गुरुवार

केशव टाइम्स
डिजिटल संस्करण

गैस एजेंसियों पर जिलाधिकारी का सख्त रुख, देरी पर जताई नाराजगी 2

प्रमुख खबरें : दिल्ली ■ पटना ■ बक्सर ■ शाहाबाद ■ मगध

आपकी आवाज

■ सारण ■ मिथिलांचल ■ चंपारण ■ पूर्वांचल ■ लखनऊ

एक नजर

ईरान में अभी भी 1000 भारतीय

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच करीब एक हजार भारतीय अभी भी ईरान में मौजूद हैं। जबकि, खाड़ी देशों में रहने वाले 23 हजार छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की अंतिम परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में दी। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, करीब एक हजार लोग अभी भी ईरान में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनमें से सभी वहां से निकलना चाहते हों। कांग्रेस नेता ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कक्षा 10 और 12 के छात्र अपनी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं नहीं दे सके। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि उनकी समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मुझे बताया गया कि विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है, ताकि उन 23 हजार छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके, जो परीक्षा नहीं दे पाए। थरूर ने कहा कि बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी सांसदों ने हालात, उसके प्रभाव, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों और तेल-गैस आपूर्ति को लेकर सवाल उठाए।

मनी गेम्स पर देशभर में प्रतिबंध वाला नया कानून लागू

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि वह देश में सुरक्षित, जिम्मेदार और जवाबदेह ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रतिबद्ध है। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में बताया कि इस उद्देश्य से ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन अधिनियम, 2025 लागू किया गया है। इस कानून के तहत पैसे से जुड़े ऑनलाइन खेलों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। मुरुगन ने कहा कि इस कानून का मकसद ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देना है, जबकि पैसे से जुड़े ऑनलाइन खेलों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध हर तरह के खेलों पर लागू है, चाहे वे भाग्य आधारित हों, कौशल आधारित हों या दोनों का मिश्रण हों।

बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम से होगी वोटिंग

- हर जिले के जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में नामित कर दिया गया
- पंचायत आम चुनाव की वोटिंग नवंबर-दिसंबर 2026 के बीच कराई जा सकती है

एजेंसी। पटना

बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए सभी जिलों में अधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने हर जिले के जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में नामित कर दिया है। यानी अब जिले में पंचायत चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी डड के कंधों पर होगी। इस फैसले के साथ ही चुनावी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू माना जा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सिर्फ डीसी ही नहीं, बल्कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की जिम्मेदारी भी दी है। इससे चुनावी कार्यों के संचालन में सहूलियत होगी और दोनों स्तर पर समन्वय बेहतर तरीके से हो सकेगा। आयोग ने इस आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेज दी है, ताकि हर स्तर पर तैयारी सुनिश्चित की जा सके। पंचायत चुनाव के लिए मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 6 बैलेट यूनिट होंगी, जबकि कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगी।

नवंबर-दिसंबर में हो सकती है वोटिंग

सूत्रों के अनुसार, बिहार में पंचायत आम चुनाव की वोटिंग नवंबर-दिसंबर 2026 के बीच कराई जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों से यह साफ हो गया है कि चुनाव समय पर कराने की योजना है। गांव की सरकार चुनने को लेकर राज्यभर में राजनीतिक हलचल भी धीरे-धीरे तेज होने लगी है।

पहली बार ईवीएम से होगा मतदान

इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से कराए जाएंगे। अब तक इन चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार तकनीक का उपयोग किया जाएगा. यह बदलाव चुनाव प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बनाने के लिए किया जा रहा है।

खड़गे बोले- देवगौड़ा ने मोहब्बत हमसे, शादी पीएम मोदीजी से की

एजेंसी। नई दिल्ली

राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी स्पीच के दौरान पूर्व पीएम और जनता दल (सेक्युलर) के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा का जिक्र किया। उन्होंने कहा- मुझे पता नहीं कि उन्हें (देवगौड़ा) क्या हुआ। उन्होंने मोहब्बत हमसे की, लेकिन शादी मोदीजी के साथ की। खड़गे की बात सुनकर राज्यसभा में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी भी हंसते हुए नजर आए। खड़गे की टिप्पणी पर देवगौड़ा ने देर शाम एक लेटर लिखकर जवाब दिया और बताया जब खड़गे सदन में बोल रहे थे, तब वे वहां मौजूद नहीं थे। देवगौड़ा ने आगे लिखा- अगर मैं अपने मित्र खड़गे को उसी शादी वाली भाषा में जवाब दूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस के साथ जबरन शादी में था, लेकिन वह एक अपमानजनक रिश्ता था, इसलिए मुझे उनसे तलाक लेना पड़ा। अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से रिटायर हो रहे 59 सांसदों को विदाई दी गई। इनमें पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, सभापति हरिवंश, आरपीआई नेता रामदास आठवले शामिल हैं। हालांकि पवार और आठवले राज्यसभा के लिए फिर चुन लिए गए हैं।

दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों ने 10 लोगों का रेक्स्यू किया

दिल्ली में चार मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 9 लोगों की मौत

■ 30 फायर ब्रिगेड से आग पर पाया काबू

एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली के पालम स्थित साध नगर में एक रिहायशी 4 मंजिला बिल्डिंग में बुधवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। 2 लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों ने 10 लोगों का रेक्स्यू किया है। इनमें 3 लोग घायल हैं। करीब 30 फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेजी से फैल गई। इमारत में उस समय 10-15 लोग मौजूद थे। इनमें कुछ शव बरामद किए जा चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े और कॉस्मेटिक सामान के स्टोरेज के लिए किया जा रहा था। सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर लोग रहते थे। चौथे फ्लोर पर एक टिन शेड बना हुआ था। आग की लपटें वहां तक पहुंच गई थीं।घटना में मारे गए 8 लोगों के शव मणिपाल अस्पताल और एक महिला का शव अस्पताल लाया गया था। घायलों में दो का इलाज कक्कक अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक व्यक्ति को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में प्रवेश (33), कमल (39), आशु (35), लाडो (70), हिमांशी (22), दीपिका (28) और तीन नाबालिग लड़कियां (15, 6 और 3 साल) शामिल हैं। अनिल (32) और 2 साल की एक बच्ची अस्पताल में भर्ती हैं। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सचिन (29) झुलस चुके हैं।

नीचे लपटें और ऊपर घना धुआं था

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी एस. के. दुआ ने बताया कि आग सुबह करीब 7 बजे लगी थी। जब हमारी पहली टीम मौके पर पहुंची, तो नीचे आग की लपटें और ऊपर घना धुआं था। हमारे पहुंचने से पहले दो लोग इमारत से कूद गए थे, जिन्हें लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। अधिकारी के मुताबिक, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग घायल हैं। आग पर अब पूरी तरह काबू पा लिया गया है, हालांकि कूलिंग ऑपरेशन जारी है। इसके बाद बिल्डिंग में एक बार फिर सर्च और रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं, फायर सर्विस के डिप्टी इंस्पेक्टर विक्की रांगा ने कहा बताया कि वे 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गए थे। तब तक दिल्ली फायर सर्विस और अन्य एजेंसियां आग बुझाने में लगी थीं। बिल्डिंग अंदर से काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ी चुनौती है। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है।

प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का किया एलान

पालम आग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि घायलों को 50 हजार दिए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी घटना पर दुख जताया और पार्टी कार्यकताओं से पीड़ितों की मदद करने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को फटकार

रेड के दौरान मुख्यमंत्री का दखल ठीक नहीं

एजेंसी। नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री का मौके पर पहुंचना और हस्तक्षेप करना अच्छी स्थिति नहीं है। अदालत ने यह भी पूछा कि ऐसे असामान्य हालात में केंद्रीय एजेंसी के पास क्या कोई उपाय नहीं होना चाहिए। यह मामला उस समय का है जब प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव से पहले के दफ्तरों पर छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई थीं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह हस्तक्षेप करना सत्ता का गंभीर दुरुपयोग है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, ममता बनर्जी छापेमारी के दौरान चुनाव रणनीतिकार कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पहुंचीं। एजेंसी का आरोप है कि वह वहां से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई दस्तावेज अपने साथ ले गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने इसे जांच में बाधा डालने वाला कदम बताया और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और इसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए करवाया। उनका कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। ईडी ने ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एजेंसी का कहना है कि यह कार्रवाई कोयला घोटाला मामले से जुड़ी थी और पूरी तरह सबूतों के आधार पर की गई थी। ईडी ने साफ किया कि यह किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि जांच के तहत की गई कार्रवाई थी।

पोखरण में पहली बार निजी कंपनी ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण

पोखरण । रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। राजस्थान के पोखरण में सोलर ग्रुप ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स का सफल परीक्षण करके रक्षा क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। कंपनी ने पहली बार पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट के दो उत्पादन बैचों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह महत्वपूर्ण परीक्षण राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। सोलर ग्रुप ने बताया कि इस दौरान कुल 24 पिनाका एनहैंस्ड रॉकेट्स का परीक्षण किया गया। इन रॉकेट्स की सटीकता, स्थिरता और मारक क्षमता को परखा गया। कंपनी के अनुसार, सभी रॉकेट्स ने मैदानी परिस्थितियों में असाधारण रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह देश में पहली बार है जब पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स के उत्पादन बैचों का परीक्षण किसी निजी कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। यह सफलता रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रमाण है। इससे सेना को हथियार और गोला-बारूद की सप्लाई में तेजी आएगी। पिनाका एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो बहुत कम समय में एक बड़े इलाके में दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। एक्सटेंडेड रेंज यानी बढ़ाई गई मारक क्षमता वाले ये रॉकेट और भी घातक हैं। अब सोलर ग्रुप जैसी निजी कंपनियां इनके उत्पादन में मदद कर रही हैं, जिससे सेना की ताकत और बढ़ेगी।

पाइपलाइन सुरक्षा पर फोकस: छतनवार में मॉकड्रिल से सिखाए गए आपदा प्रबंधन के गुर

अग्निशमन व एसडीआरएफ की संयुक्त पहल, ग्रामीणों और कर्मचारियों को दिया गया रेस्क्यू व सुरक्षा प्रशिक्षण

केटी न्यूज/डुमरांव

अनुमंडल क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के छतनवार गांव स्थित आईओसीएल की मुख्य तेल पाइपलाइन पर एक व्यापक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पाइपलाइन में संभावित रिसाव या आग लगने जैसी आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी को परखना और लोगों को प्रशिक्षित करना था।

मॉकड्रिल में डुमरांव अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ बिहटा की संयुक्त टीम ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान एक काल्पनिक आपात स्थिति तैयार की गई, जिसमें पाइपलाइन में रिसाव के बाद आग लगने की स्थिति को दर्शाया गया। इस दौरान टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने, क्षेत्र को सुरक्षित करने और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी शिखा कुमारी ने बताया कि ऐसी मॉकड्रिल का उद्देश्य केवल अभ्यास नहीं, बल्कि लोगों में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में घबराहट सबसे बड़ी समस्या होती है, इसलिए लोगों को सही समय पर सही कदम उठाने की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

उन्होंने कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों को निर्देश दिया कि पाइपलाइन से जुड़ी किसी भी असामान्य गतिविधि या रिसाव की स्थिति में तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दें। त्वरित सूचना से ही बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इसके साथ ही, उन्होंने आग बुझाने के प्राथमिक उपायों और सुरक्षा उपकरणों जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के सही उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

एसडीआरएफ टीम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन करते हुए बताया कि आपातकाल में किस तरह तेजी, समन्वय और तकनीकी दक्षता के साथ कार्रवाई की जाती है। उन्होंने घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और भीड़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझाया।

मॉकड्रिल के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्हें आपदा के समय संयम बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे नियमित अभ्यास से न केवल आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत होता है, बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है, जिससे जनहानि की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की।

गैस एजेंसियों पर जिलाधिकारी का सख्त रुख, देरी पर जताई नाराजगी

तीन दिन में डिलीवरी का आदेश, सूचना पट्ट नहीं रखने पर कार्रवाई के संकेत

केटी न्यूज/बक्सर

जिलाधिकारी साहिला ने बक्सर नगर क्षेत्र की गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था की हकीकत परखी और लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मेसर्स कुँवर ज्योति गैस एजेंसी (चरित्रवन) एवं मेसर्स सोनामति इंडेन गैस एजेंसी (लालगंज) के गोदामों की स्थिति का जायजा लिया गया। कुँवर ज्योति गैस एजेंसी के दानी कुटिया स्थित गोदाम में जांच के दौरान सामने आया कि पिछले दो दिनों से सिलेंडर वाहन नहीं पहुंचने के कारण वितरण बाधित है। वर्तमान में 2446 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है। एजेंसी प्रबंधन ने बताया कि 11 मार्च तक की बुकिंग का वितरण किया जा चुका है और वाहन उपलब्ध होते ही 12 मार्च तक की बुकिंग पूरी की जाएगी। इस पर डीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए

कहा कि बुकिंग के एक सप्ताह बाद गैस उपलब्ध कराना गंभीर लापरवाही है, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। डीएम ने निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को अधिकतम तीन दिनों के भीतर होम डिलीवरी के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जाए। साथ ही किसी भी परिस्थिति में गोदाम से सीधे वितरण पर रोक लगाने को कहा गया। स्टॉक और आपूर्ति तिथि की जानकारी सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का भी आदेश दिया गया। वहीं, सोनामति इंडेन गैस एजेंसी के लालगंज गोदाम में 2600 बुकिंग लंबित पाई गई। यहां 13 मार्च तक की बुकिंग का वितरण जारी था और 14 मार्च तक की आपूर्ति वाहन मिलने पर करने की बात कही गई। हालांकि, निरीक्षण में सूचना पट्ट नहीं पाया गया, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एजेंसी संचालक से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

गैस एजेंसियों पर प्रशासन की सख्ती, 27 केंद्रों की सघन जांच

बक्सर। जिले में रसोई गैस की संभावित जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी साहिला और पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के संयुक्त निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने बुधवार को जिलेभर की गैस एजेंसियों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस कार्रवाई से एजेंसी संचालकों में हड़कंप मच गया। प्रशासन द्वारा कुल 27 गैस एजेंसियों की जांच के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। प्रत्येक टीम में एक वरीय दंडाधिकारी या पदाधिकारी के साथ एक पुलिस अधिकारी को शामिल किया गया, ताकि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरी की जा सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्धारित प्रपत्र के आधार पर एजेंसियों की कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच की। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि एजेंसियों पर मूल्य सूची, कार्य के घंटे और स्टॉक की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। कई स्थानों पर इन मानकों की जांच को लेकर अधिकारियों ने सख्ती दिखाई और आवश्यक निर्देश भी दिए। जांच के दौरान डिलीवरी व्यवस्था को भी परखा गया। अधिकारियों ने देखा कि डिलीवरी कर्मियों के पास सिलेंडर का वजन करने के लिए वेईंग स्केल उपलब्ध है या नहीं। साथ ही उपभोक्ताओं के सामने सिलेंडर का वजन और लीकेज की जांच की जा रही है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। सुरक्षा मानकों को लेकर भी टीमों ने एजेंसियों की गंभीरता को परखा। निरीक्षण में यह देखा गया कि प्रतिष्ठानों पर फर्स्ट एड बॉक्स, शिकायत पुस्तिका और आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं या नहीं। कई जगहों पर डिलीवरी कर्मियों के वर्दी और परिचय पत्र की भी जांच की गई, जिससे उनकी पहचान और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अभियान की खास बात यह रही कि अधिकारियों ने केवल कागजी जांच तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सीधे उपभोक्ताओं से संवाद भी किया।

एमवी कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य प्रो. रामाशीष सिंह का निधन, शैक्षणिक जगत में शोक की लहर

85 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस, विद्यार्थियों और सहकर्मियों के लिए थे प्रेरणास्रोत

केटी न्यूज/बक्सर

महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय (एमवी कॉलेज), बक्सर के पूर्व प्रभारी प्राचार्य एवं भौतिक विज्ञान विभाग के वरिष्ठ शिक्षक प्रो. (डॉ.) रामाशीष सिंह का बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे 85 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही महाविद्यालय परिवार सहित पूरे शैक्षणिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

प्रो. सिंह ने अपने लंबे शैक्षणिक जीवन में शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वर्ष 2007 में उन्होंने महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संस्थान को नई दिशा दी। वे न केवल एक कुशल शिक्षक थे, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में

भी जाने जाते थे। उनका सरल स्वभाव, कर्तव्यनिष्ठा और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण उन्हें सभी के बीच विशेष बनाता था।

उनके निधन पर महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य प्रो. (डॉ.) कृष्णा कान्त सिंह के नेतृत्व में शोकसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

शोकसभा को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रो. कृष्णा कान्त सिंह ने कहा कि प्रो. रामाशीष सिंह का निधन महाविद्यालय परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी विद्वता, अनुशासनप्रियता और शिक्षा के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो. (डॉ.) श्याम जी मिश्रा, प्रो. (डॉ.) सुरेन्द्र सिंह सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

प्रो. रामाशीष सिंह का जाना शिक्षा जगत के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है।

डीजे व भड़काऊ नारेबाजी पर रोक, शाम 5 बजे तक शोभायात्रा समाप्त करने का निर्देश

नावानगर। आगामी ईद, रामनवमी और चैती छठ पर्व को लेकर स्थानीय थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में प्रशासन ने सुरक्षा और सौहार्द को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। थानाध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नावानगर व केसठ प्रखंड के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बुद्धिजीवी शामिल हुए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभायात्रा को हर हाल में शाम पांच बजे तक समाप्त करना होगा। साथ ही, शोभायात्रा के दौरान पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने डीजे और तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात भी दोहराई। ईद पर्व को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी स्थिति में ऐसी गतिविधि या नारेबाजी न हो, जिससे किसी समुदाय की भावना आहत हो।

चौसा में मच्छरों पर वार : नगर पंचायत ने तेज किया गया छिड़काव अभियान

फॉगिंग मशीन खराब, स्प्रे के जरिए शुरू हुआ अभियान सभी 14 वार्डों में चरणबद्ध कार्रवाई की तैयारी

केटी न्यूज/बक्सर

चौसा नगर क्षेत्र में तेजी से बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए नगर पंचायत ने आखिरकार सक्रिय कदम उठाते हुए विशेष छिड़काव अभियान की शुरूआत कर दी है। मौसम में बदलाव के साथ मच्छरों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की है।

हालांकि तकनीकी समस्या के कारण फॉगिंग मशीन फिलहाल काम नहीं कर रही है, लेकिन अभियान को रोकने के बजाय नगर पंचायत ने

वैकल्पिक व्यवस्था अपनाते हुए स्प्रे मशीन के माध्यम से दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। अभियान की शुरूआत वार्ड संख्या 1 और 2 से की गई, जहां टीमों ने घर-घर पहुंचकर और नालियों के आसपास विशेष रूप से छिड़काव किया। स्वच्छता पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बदलते मौसम में मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी खतरे को कम करने के उद्देश्य से नगर पंचायत ने सभी 14 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से छिड़काव कराने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी बताया कि फॉगिंग मशीन की मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जा रहा है, ताकि जल्द ही नियमित रूप से धुआं कर मच्छरों को नियंत्रित किया जा सके।

नगर पंचायत ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि यही मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है। खासकर कूलर, गमले, पुराने टायर और छतों पर जमा पानी को नियमित रूप से साफ करने की सलाह दी गई है।

साथ ही, छिड़काव के दौरान घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर रखने की अपील की गई है, ताकि दवा का असर अधिक प्रभावी हो सके।

नगर पंचायत के इस अभियान से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यदि अभियान इसी गति से चलता रहा, तो आने वाले दिनों में मच्छरों के प्रकोप पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

लंबे इंतजार के बाद फिर शुरू हुआ स्टेशन रोड का मरम्मत कार्य, दिनभर जाम से थमे पहिए

छह माह से रूक-रूक कर चल रहा काम, पुलिस नदारद—स्कूली बच्चे और यात्री सबसे ज्यादा परेशान

केटी न्यूज/डुमरांव

स्टेशन रोड पर चल रहे मरम्मतिकरण कार्य ने लोगों की परेशानी कम करने के बजाय और बढ़ा दी है। पिछले छह माह से रूक-रूक कर हो रहे इस कार्य के कारण बुधवार को पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। मां डुमरेजिन मंदिर मोड़ से लेकर पुराना भोजपुर चौक तक सड़क मरम्मत के लिए करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब तक काम अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरूआत में सड़क के गड्ढों को भरने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। बीच-बीच में काम शुरू होता है और फिर बंद हो जाता है, जिससे सड़क की हालत और बदतर हो गई है। बुधवार को महरौरा मोड़ के पास सड़क की खुदाई कर दी गई, जिससे रास्ता संकरा होकर वन-वे जैसा हो गया। इस कारण बड़े वाहनों के फंसने से जाम और विकराल हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और यात्रियों को झेलनी पड़ी। कई बसें जाम में फंसी रहीं, जिससे बच्चे घंटों परेशान होते रहे। स्थिति यह रही कि कुछ अभिभावक खुद जाम में फंसे वाहनों तक पहुंचकर अपने बच्चों का हालचाल लेने लगे। जाम के दौरान पुलिस व्यवस्था पूरी तरह नदारद दिखी। महरौरा मोड़ पर सामान्यतः दो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां कोई तैनाती नहीं है। नहर रोड और मुख्य सड़क के संगम पर तीन दिशाओं से वाहनों का दबाव जाम को और बढ़ा देता है।

घंटों जाम लगे रहने के बावजूद जब कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा, तो स्थानीय लोग खुद ही व्यवस्था संभालते नजर आए। अभिभावकों ने भी इसमें सहयोग किया। आक्रोशित लोगों ने वरीय अधिकारियों को फोन कर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने तत्काल जाम हटाने का निर्देश दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सड़क मरम्मत कार्य को लगातार और तेजी से पूरा कराया जाए तथा जाम से निजात के लिए स्थायी यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

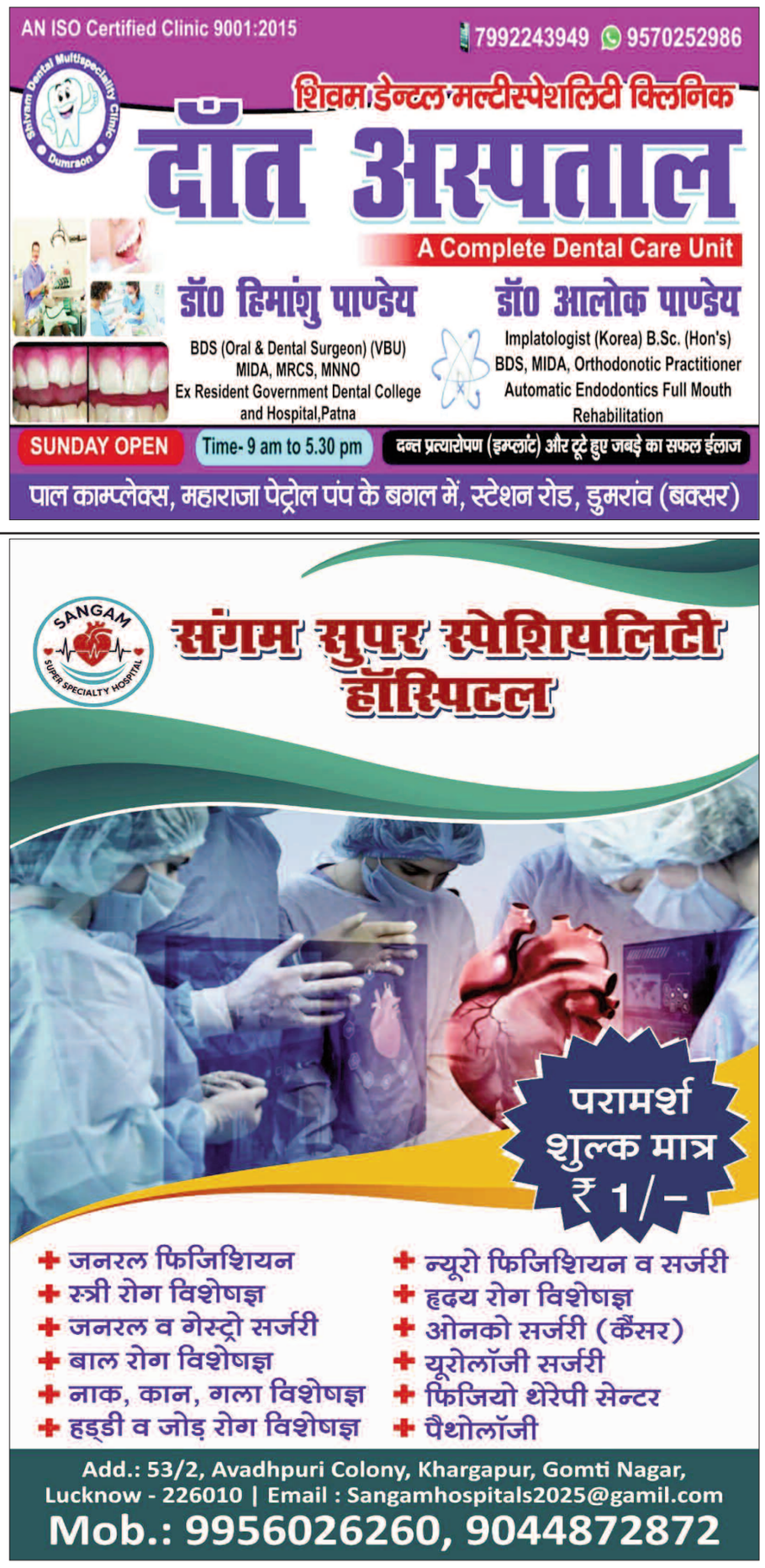

राजपुर के लाल ने सिक्किम में लहराया परचम, राष्ट्रीय मंच पर शोध प्रतिभा का मिला सम्मान

- **पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत पर प्रभावशाली व्याख्यान, राज्यपाल ने किया सम्मानित**

केटी न्यूज/राजपुर

राजपुर गांव के एक युवा शोधार्थी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोधरत विश्वजीत कुमार त्रिगुण को गंगटोक में आयोजित एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परिसंवाद में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें सिक्किम के माननीय राज्यपाल के हाथों प्राप्त हुआ, जिसने उनकी उपलब्धि को और भी गौरवपूर्ण बना दिया। गंगटोक स्थित ह्यलोक भवनह्ल में आयोजित इस दो दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का विषय था– ह्लपूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक वैभव और साहित्यह्ल। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय हिंदी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) और सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। देशभर से आए विद्वानों और शोधार्थियों के बीच विश्वजीत ने

अपने शोध आधारित व्याख्यान से अलग पहचान बनाई। अपने संबोधन में उन्होंने ह्लपूर्वोत्तर में वैष्णव भक्ति आंदोलन और नाट्य परंपराह्ल विषय को बेहद गहराई और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक जड़ों, वहां के भक्ति आंदोलन और नाट्य परंपरा के ऐतिहासिक विकास को उदाहरणों के साथ समझाया। उनके व्याख्यान में न केवल अकादमिक गहराई थी, बल्कि प्रस्तुति की सहजता और प्रभावशाली शैली ने भी सभी को प्रभावित किया।

कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों, विद्वानों और मुख्य अतिथि ने उनके शोध कार्य की जमकर सराहना की। यही नहीं, उनके विचारों ने पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर भी दिया। विश्वजीत कुमार त्रिगुण, राजपुर निवासी विनय त्रिगुण के पुत्र हैं और वर्तमान में वे ह्लशिवपूजन सहाय के साहित्य में युगबोधह्ल विषय पर शोध कर रहे हैं। उनकी इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि छोटे गांवों से निकलकर भी युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। पूर्व मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह, अभिषेक त्रिगुण, मनोज त्रिगुण, डब्बू सिंह सहित कई समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

राजपुर का यह होनहार युवा आज कई छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया है, जो बड़े सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट : ईद, चैती छठ और रामनवमी पर कड़ी निगरानी, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

- **शांति समिति की बैठक में डीएम ने दिए सख्त निर्देश, जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य और संवेदनशील स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था**

केटी न्यूज/बक्सर

जिले में आगामी ईद-उल-फितर, चैती छठ और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी, शांति समिति के सदस्य तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।

बैठक की शुरूआत में जिलाधिकारी ने मार्च माह में पड़ने वाले प्रमुख पर्वों की जानकारी देते हुए बताया कि 20 और 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 24 और 25 मार्च को चैती छठ तथा 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। इसके साथ ही वर्तमान में रमजान माह चलने के कारण मस्जिदों में नमाज के दौरान भीड़ को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

ईद-उल-फितर को लेकर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास साफ-सफाई, पेयजल और रोशनी की समुचित व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को इस दिशा में जिम्मेदारी सौंपी गई है। 20 मार्च को अंतिम जुम्मे की नमाज के दौरान भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

चैती छठ को लेकर प्रशासन की तैयारी और भी व्यापक रहेगी। गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित आवागमन और गोताखोरों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह सक्रिय रखने पर जोर दिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सके।

रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन ने सबसे सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जुलूस निकालने के लिए शत-प्रतिशत लाइसेंस अनिवार्य होगा और जुलूस केवल पूर्व निर्धारित मार्गों से ही निकाले जाएंगे। जुलूस मार्ग का पूर्व में भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर और डुमरांव को दिया गया है।

इसके साथ ही जुलूसों में भड़काऊ गाने, नारेबाजी और प्रतिबंधित हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। किसी भी ऐसी झांकी या दृश्य के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे किसी समुदाय, जाति या वर्ग की भावनाएं आहत हो सकती हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रामनवमी के अवसर पर डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस निर्णय को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही नियंत्रण कक्ष स्थापित कर पूरे जिले में विधि-व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी।

जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों से अपील की कि वे प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें और समाज में भाईचारा बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि सभी त्योहार आपसी सद्भाव और शांति का संदेश देते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और प्रशासन को सहयोग करें।

एक नजर

अस्मिता लीग में कुप्रबंधन के आरोप जांच की उठी मांग

चौसा। बक्सर में महिलाओं को खेल के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित ह्यअस्मिता लीग 2026ह्ल अब सवालों के घेरे में आ गई है। जागृति युवा क्लब पवनी के अध्यक्ष संजय गोंड़ ने आयोजन में भारी अनियमितता और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च तथा 13-14 मार्च को किला मैदान, बक्सर में खेलो इंडिया और जिला प्रशासन के सहयोग से बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित होनी थी, जिसमें लगभग 500 महिला खिलाड़ियों की भागीदारी प्रस्तावित थी। लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग रही। कार्यक्रम न तो तय मानकों पर खरा उतरा और न ही व्यवस्थाएं संतोषजनक दिखीं। संजय गोंड़ के अनुसार आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे जिला युवा अधिकारी द्वारा समय रहते पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। न ही जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया, जिसके कारण पूरे आयोजन की व्यवस्था चरमरा गई। उन्होंने आरोप लगाया कि खेल प्रतियोगिता के दौरान कई स्थानों पर अव्यवस्था, संसाधनों की कमी और प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आई। मामले को और गंभीर बनाते हुए उन्होंने वित्तीय अनियमितता की भी आशंका जताई। उनका कहना है कि प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित 25 हजार रुपये की राशि में से मात्र 12,500 रुपये ही भुगतान किया गया, जिससे संबंधित समितियों और खिलाड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी कारण राजपुर और चौसा प्रखंड की टीमों ने नाराजगी जताते हुए प्रतियोगिता से दूरी बना ली। युवा क्लब अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है, बल्कि सरकारी योजनाओं की साख पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो और खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल सके।

जिला स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, 12 लोगों ने किया रक्तदान

बक्सर। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल लगभग 12 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। इस आयोजन में ब्लड बक्सर की अहम भूमिका रही। शिविर का विधिवत उद्घाटन सिविल सर्जन एवं ब्लड बक्सर के सचिव डॉ. श्रवण तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के कर्मियों सहित शहर के कई लोगों ने भाग लिया और रक्तदान के प्रति जागरूकता दिखाई। रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. श्रवण तिवारी ने युवाओं को रक्तदान के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है और इसे महादान के रूप में माना जाता है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, बल्कि यह एक भ्रांति है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि नियमित अंतराल पर रक्तदान करने से न केवल जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभकारी होता है। शिविर के माध्यम से युवाओं में सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में जागरूकता बढ़ती है और अधिक लोग रक्तदान के लिए आगे आते हैं। आयोजकों ने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके।

20 मार्च को बक्सर में विशेष रोजगार शिविर, सैकड़ों पदों पर होगा चयन

केटी न्यूज/बक्सर

जिला नियोजनालय, बक्सर के तत्वावधान में आगामी 20 मार्च को विशेष रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह शिविर संयुक्त श्रम भवन, आईटीआई फील्ड, बक्सर स्थित नियोजनालय परिसर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक संचालित होगा। इस शिविर में विभिन्न निजी कंपनियां भाग लेकर अभ्यर्थियों का योग्यतानुसार स्थल पर ही चयन करेंगी। शिविर में भाग लेने वाली प्रमुख कंपनियों में फाइव बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ब्लिंकिट, एमआरएफ तथा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। फाइव बीपीओ कंपनी द्वारा कॉलिंग (आवक/जावक कॉल) कार्य हेतु 300 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा संग्रह पदाधिकारी के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए बाइक अनिवार्य होगी।

इसी प्रकार ब्लिंकिट कंपनी द्वारा बिलिंग, पैकिंग एवं डिलीवरी कर्मियों के 100 पदों पर चयन किया जाएगा, जिसमें आठवीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। एमआरएफ कंपनी उत्पादन/ऑपरेटर के 150 पदों पर भर्ती करेगी, जबकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा असेंबलर सहायक के 500 पदों पर चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान लगभग 13,500 रुपये से 19,500 रुपये के बीच निर्धारित है। कुछ कंपनियों द्वारा कार्यस्थल पर भोजन एवं परिवहन की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जाएगी। रोजगार शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का जिला नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी अब तक निबंधित नहीं हो सके हैं, वे राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा एवं आधार कार्ड के साथ शिविर में उपस्थित होकर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी ने जिले के सभी बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस विशेष रोजगार शिविर में भाग लेकर रोजगार के अवसर प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियुक्ति से संबंधित सभी शर्तों के लिए संबंधित नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे, जबकि नियोजनालय की भूमिका केवल सुविधा प्रदान करने की है।

डुमरांव शिविर में 30 दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड के लिए रेफर

- **दो दिवसीय शिविर में 50 का पंजीकरण, 13 नए और 17 पुराने दिव्यांगों को जिला भेजा गया**

केटी न्यूज/डुमरांव

दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डुमरांव प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बुनियाद केंद्र में आयोजित दो दिवसीय शिविर का बुधवार को समापन हो गया। शिविर के अंतिम दिन कुल 50 दिव्यांगों का पंजीकरण कर उनकी चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें से 30 दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए जिला मुख्यालय बक्सर रेफर किया गया।

शिविर में चिकित्सकों की टीम द्वारा विस्तृत जांच की गई। टीम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) प्रभारी डॉ. आर.बी. प्रसाद, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सौरव तथा फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. विकास कुमार शामिल रहे। चिकित्सकों ने दिव्यांगों की स्थिति का आकलन कर पात्र लाभार्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए चिन्हित किया।

बुनियाद केंद्र के प्रबंधक कश्मीरी चौधरी ने बताया कि 17 एवं 18 मार्च को आयोजित इस शिविर में कुल 50 दिव्यांगों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से जांच के बाद 30 को यूडीआईडी कार्ड के लिए उपयुक्त पाया गया। इनमें 13 नए और 17 पुराने दिव्यांग शामिल हैं। सभी चयनित लाभार्थियों को बक्सर भेजा गया है, जहां गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अंतिम जांच के बाद उनका यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। शिविर में न केवल पंजीकरण और जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई, बल्कि कई अभिभावकों को यूडीआईडी कार्ड से संबंधित जानकारी भी दी गई।

इस दौरान बुनियाद केंद्र के केश प्रबंधक मुन्ना राम, हीयरिंग एवं स्पीच विशेषज्ञ ममता कुमारी, ऑपरेटर कार्तिक कुमार सहित अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे। शिविर के सफल आयोजन से दिव्यांगजनों और उनके परिजनों में संतोष देखा गया।

विश्वकर्मा कारीगरों को मिला नया मंच बक्सर में तीन दिवसीय हस्तशिल्प मेला शुरू

- **पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा, कारीगरों को बाजार से जोड़ने की पहल**

केटी न्यूज/बक्सर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कार्यालय, पटना की ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बक्सर के बाजार समिति रोड में बुधवार से तीन दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का शुभारंभ किया गया। यह मेला 18 से 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को एक सशक्त मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें, उनकी बिक्री सुनिश्चित हो और उन्हें

व्यापक बाजार से जुड़ने का अवसर मिले। इस पहल से कारीगरों को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता मिल रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक निदेशक (ग्रेड-1) एस. के. अग्निहोत्री ने किया। उन्होंने उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह योजना कारीगरों के कौशल विकास और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस अवसर पर सहायक निदेशक संतोष कुमार साहू ने मेले की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय कारीगरों को न केवल बाजार मिलता है, बल्कि उनके उत्पादों की पहचान और ब्रांड निर्माण में भी सहायता मिलती है। इससे उनकी आय में भी वृद्धि होती है। जिलाधिकारी साहिला ने डुमरांव के प्रसिद्ध सिंधोरा निर्माण जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसी कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन्हें संरक्षित करना और आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कारीगरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने हुनर को नई तकनीकों से जोड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी एवं अन्य अतिथियों ने लगभग 60 विश्वकर्मा कारीगरों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कारीगरों को अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करने और ई-मार्केट प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे बड़े बाजार तक पहुंच बना सकें। इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के संयुक्त निदेशक सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में हर्ष, विद्या भूषण पाठक, अंकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, अयोध्या चौधरी और अभय कुमार सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह तीन दिवसीय मेला कारीगरों के लिए एक सुनहरा अवसर बनकर सामने आया है, जहां वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के साथ-साथ सीधे ग्राहकों से जुड़ रहे हैं। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है।

समयबद्ध अनुसंधान से बढ़ा भरोसा, राजपुर पुलिस की कार्यशैली बनी मिसाल

केटी न्यूज/राजपुर

राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिसिंग के एक सकारात्मक पहलू ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आमतौर पर लंबित मामलों और धीमी जांच को लेकर उठने वाले सवालों के बीच यहां के पुलिस पदाधिकारियों ने समयबद्ध अनुसंधान कर एक नई मिसाल पेश की है। त्वरित कार्रवाई और सटीक साक्ष्य संकलन के कारण कई मामलों में तेजी आई है, जिससे पीड़ितों को न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है। थाना अध्यक्ष निवास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सुनिश्चित किया कि केस डायरी समय पर तैयार हो और अनुसंधान में अनावश्यक देरी न हो। इसी क्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों एसआई सुनील कुमार साह गोंड, अनीशा भारती, वकार अहमद गौसी, शिवकुमार मंडल, प्रमोद कुमार और एएसआई अनिल

कुमार–को सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी टीम की कार्यशैली को दर्शाता है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यदि जांच सही दिशा में और तय समय में पूरी हो, तो न्याय प्रक्रिया स्वतः मजबूत हो जाती है। राजपुर थाना की टीम ने इसी सिद्धांत को अपनाते हुए काम किया है।

इस पहल का असर स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों और नागरिकों का कहना है कि जब पुलिस तेजी और पारदर्शिता से काम करती है, तो जनता का भरोसा बढ़ता है। साथ ही अपराधियों में भी कानून का भय बना रहता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल यदि अन्य थानों में भी लागू हो, तो न्याय प्रणाली में लंबित मामलों का बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है। राजपुर पुलिस की यह कार्यशैली न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि जनता-पुलिस संबंधों को भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रोहतास एडीएम ने शांति समिति की बैठक में दिए कड़े निर्देश

केटी न्यूज/रोहतास

नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के समीप स्थित अजीत ऑडिटोरियम हॉल में बुधवार को आगामी ईद,चैती छठ और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रोहतास एडीएम ललित भूषण रंजन ने की। बैठक में बिक्रमगंज एसडीएम प्रभात कुमार, एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह,भूमि सुधार उपसमाहर्ता संतोष कुमार मुख्य रूप से रहे। उक्त अवसर पर बिक्रमगंज नगर परिषद व अन्य नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी समेत अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि,मीडिया प्रतिनिधि,सामाजिक कार्यकर्ता, शांति समिति और पूजा समिति के सदस्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों ने पर्वो से जुड़ी अपनी समस्याएं और सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे। अधिकारियों ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। एडीएम ललित भूषण रंजन ने कहा कि सभी पर्वो को भाईचारे और शांति के साथ मनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान साफ-सफाई,पर्याप्त लाइटिंग, पेयजल व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी होनी चाहिए। उन्होंने मादक पदार्थो,शरारती तत्वों,शराबियों, सोशल मीडिया पर नकेल कसने की बातें कही । श्री रंजन ने पर्व में सीसीटीवी कैमरा,वीडियो ग्राफी व ड्रोन कैमरे से निगरानी करने की बातें कही । उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम प्रभात कुमार,एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह व भूमि सुधार उपसमाहर्ता संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि पर्वो के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है । उन्होंने कहा कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,शराब पर सख्ती,ड्रोन कैमरे, वीडियो ग्राफी व सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने की भी बातें कही । साथ ही साथ असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । संयुक्त रूप से तीनों अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । बैठक में जिला और अनुमंडल स्तर के सभी विभागों के अधिकारी,जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और समिति सदस्य मौजूद थे,जिन्होंने प्रशासन के निदेर्शों का पालन करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने सभी लोगों को पर्वो के दौरान सहयोग और सतर्क रहने की अपील की।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का चला हथौड़ा : हड़ताली अंचल अधिकारियों पर बड़ा प्रहार...एक साथ कई सीओ को किया सस्पेंड

एजेंसी। पटना

राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। सरकार ने तीन अंचलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हड़ताल पर रहने और सरकार के खिलाफ प्रचार-प्रसार करने के आरोप में पटना के पूर्व सीओ जितेंद्र कुमार पांडेय, पटना सदर के अंचलाधिकारी रजनीकांत और पूर्वी चंपारण के घोड़ासन के सीओ आनंद कुमार पर कार्रवाई की गयी है। इन तीनों को सस्पेंड किया गया है।मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हड़ताल और सरकारी आदेशों के खिलाफ प्रचार-प्रसार करना निंदनीय है, विशेषकर ऐसे समय में जब जनगणना का कार्य 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे प्रयासों से सरकारी कामकाज बाधित हो रहा है और लोगों में भ्रम तथा उत्तेजना फैल रही है। कुछ अधिकारी जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं, वे भी वर्तमान राजस्व सेवा अधिकारियों को भड़काने में भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने इस प्रकार के सार्वजनिक वक्तव्यों और अराजक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। अधिकारियों के इस प्रकार के आचरण और कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करने की घटनाओं की विस्तृत जांच कर निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि ऐसे प्रयासों से सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि जितने कार्यरत कर्मचारी हैं उनमें 50 प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं। यह रिपोर्ट एडीएम ने भेजा है। इसके बावजूद इस तरह का बयान देकर सरकार के आदेश को झुठलाने का और बरगलाने का जिसने हिमाकत की है ऐसे लोग सरकार सेवक के योग्य नहीं है। जो भी गलत बयानी करेगा तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित करेंगे। मैंने एक बार नहीं कई बार वापस आने को कहा लेकिन ये लोग मेरी बात को भी अनसुना कर दिया। जनता की समस्या का समाधान करने के बजाय ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। इन लोगों को जनता के सामने जबाव देना पड़ेगा। अगर ये मार्च क्लोजिंग के अंदर योगदान नहीं देते हैं तो ऐसे अधिकारियों को फिल्ड में काम करने के योग्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मांग रखने का और कई तरीका है आकर पहले मिलते। बिना मिले बिना बात किये आप प्रेस मीडिया में चले गये हड़ताल कर दिये और जो लोग काम पर लौट गये है उनको आप काम करने से रोकने का वातावरण बना रहे हैं। ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। जो लोग यह साजिश रच रहे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार की कोई सहानुभूति नहीं होगी। ऐसे मानसिकता के लोग जो जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो उनको सरकार की सहानुभूति कैसे मिलेगी। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस तरह के मानसिकता के लोगों के सेवा इतिहास की जानकारी हासिल की जाएगी। इस तरह के लोग हड़ताल के नाम पर अराजकता उत्पन्न करना चाह रहे हैं। महेन्द्र पाल अध्यक्ष, मोना झा और नवाजी सदस्य होंगे। इनके जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो काम पर आना चाहेंगे उनको भी काम करने का मौका मिलेगा। जो त्यागपत्र दे चुके हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। सरकारी सेवा में बाधा उत्पन्न करने का खडयंत्र कर रहे हैं। ये लोग सरकार के विरुद्ध उतेजना बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व अंचलाधिकारी पटना सदर वर्तमान में ये अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी अररिया, रजनीकांत अंचल पदाधिकारी पटना सदर, आनंद कुमार अंचलाधिकारी घोड़ासहन पूर्वी चंपारण को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय इनका स्थान निर्धारित करते हैं।

रमजान के अंतिम दिनों में एकता की मिसाल बनी सामूहिक इफ्तार पार्टी

केटी न्यूज/राजपुर

प्रखंड क्षेत्र के अकबरपुर पंचायत अंतर्गत श्रीकांतपुर मस्जिद परिसर में रमजान के पवित्र महीने के अंतिम दिनों को खास बनाने के उद्देश्य से सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें केवल एक समुदाय ही नहीं, बल्कि विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देते नजर आए। समाजसेवी एवं मुखिया प्रतिनिधि राजेश सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने रमजान की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह महीना त्याग, संयम और इबादत का प्रतीक है। इस दौरान अल्लाह की विशेष रहमत प्राप्त होती है और इंसान को नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है।

नमाज के बाद सभी रोजेदारों ने देश में अमन-चैन, आपसी सौहार्द और समाज की तरक्की के लिए दुआ मांगी। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाते हैं।

इफ्तार पार्टी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की भी सक्रिय भागीदारी रही। सरपंच ललन यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं।

कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और भविष्य में भी इसी तरह मिल-जुलकर रहने का संकल्प लिया।

शिवपुर : कड़ी सुरक्षा के बीच शिवपुर पंचायत पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न

बूथों पर 50 .51प्रतिशत मतदाताओं ने किया मदतान

केटी न्यूज/रोहतास

प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुर पैक्स चुनाव बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। निर्धारित समयानुसार मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक चला। चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया और पूरे दिन मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही । मतदान के लिए राजकीयकृत मध्य विद्यालय शिवपुर को केंद्र बनाया गया था,जहां कुल तीन बूथ–12, 12(क) और 12(ख) स्थापित किए गए थे । मतदान की प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई गई । इस चुनाव में कुल 1445 मतदाता थे,जिनमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे । सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग समय पर मतदान केंद्र पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे। चुनाव के दौरान वरीय अधिकारियों की सक्रियता भी लगातार बनी रही । एसडीएम प्रभात कुमार,बिक्रमगंज पुलिस इंस्पेक्टर शेर सिंह यादव, बिक्रमगंज थानाध्यक्ष ललन कुमार, काराकाट थानाध्यक्ष विवेक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मतदान केंद्र का निरीक्षण करते रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। वहीं निवार्ची पदाधिकारी सह बिक्रमगंज बीडीओ सुनील कुमार गौतम,पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखे। निवार्ची पदाधिकारी सह बीडीओ सुनील कुमार गौतम ने बताया कि शिवपुर पैक्स चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ । उन्होंने जानकारी दी कि इस चुनाव में लगभग 50.51 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया । उन्होंने आगे बताया कि मतदान समाप्त होने के कुछ ही देर बाद प्रखंड कार्यालय बिक्रमगंज के परिसर में मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही प्रशासन की ओर से मतगणना को लेकर भी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं । देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के क्रम में नवादा जिले में हुआ आगमन

- लोगों ने विकास पुरुष के नारों साथ किया भव्य स्वागत
- विभिन्न योजनाओं से जुड़े विभागों का किया

केटी न्युज/नवादा

जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के क्रम में बुधवार 18 को नवादा जिला आगमन हुआ। उकार्यक्रम की शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बुधौल (नवादा) में बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं बिहार अग्निशमन सेवा से संबंधित विभिन्न स्टॉलों के निरीक्षण से की गई। जिला पदाधिकारी ने अवगत कराया कि गृह रक्षा वाहिनी का कार्यालय सह आवासीय भवन

का निर्माण कराया गया है। यह परिसर कुल 01 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। इस भवन के निर्माण पर कुल 105168750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी उक्त भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के क्रम में किया गया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बक्सर एवं जहानाबाद जिलों के कुल 228 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।इसके उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ह्यप्रगति यात्राह्ल के क्रम में पूर्व में शुभारंभ की गई योजनाओं की प्रगति का विस्तृत अवलोकन किया गया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निमार्णाधीन संजीवनी वाटिका पार्क, बुधौल (नवादा) का निरीक्षण किया गया।जिला पदाधिकारी ने बताया कि संजीवनी वाटिका का निर्माण 6.80 करोड़ रुपये की लागत से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया । इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की उपलब्धियों, योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी ली तथा आम जनता को मिलने वाले लाभों पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम के अगले चरण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 244 करोड़ रुपये की लागत से 21 योजनाओं का शिलान्यास तथा लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से 37 योजनाओं का उद्घाटन रिमोट बटन दबाकर किया गया। इन योजनाओं के माध्यम से जिले में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित होगी। इसके पश्चात आईटीआई परिसर, नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं भविष्य की विकासात्मक आकांक्षाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

एसडीएम ने अवैध घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग के विरुद्ध तेज की छापेमारी

केटी न्युज/आरा

घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर अपर जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नेतृत्व में नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर औचक छापामारी की गई। जिस जांच में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कहां-कहां अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग हो रहा प्रशासन इसके प्रति एक्शन मूड में है। जिला डीएम ने दिशा निर्देश पर एसडीएम द्वारा निरंतर छापेमारी कर अवैध घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग के विरुद्ध नकेल कसी जा रही हैं। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इसके अतिरिक्त एलपीजी गैस का अवैध भंडारण व उसकी अवैध रिफिलिंग रोक लगाई जाए। यहां दिन भर चली छापेमारी के दौरान किसी भी होटल या व्यवसायिक प्रतिष्ठान में घरेलु रसोई गैस का उपयोग होते नहीं पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कई ऐसे परिवार हैं जिनमें प्रत्येक सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन है और हर परिवार दो-दो सिलेंडर भरवाकर अपने-अपने यहां आवश्यकता से अधिक सिलेंडर रखने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों के यहां भी छापामारी करने का निर्देश सभी प्रखंड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया है। यह छापामारी अब लगातार चलेगी । यह पूछने पर कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन कब तक लगाना पड़ेगा? अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि गैस सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। गैस एजेंसी स्वयं गैस सिलेंडर घर-घर पहुंचा रही है। पीरो शहर में एक गैस एजेंसी पर अनावश्यक लोग भीड़ लगा रहे हैं जो उचित नहीं है। जबकि उपभोक्ताओं से अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुरोध किया कि अपने-अपने घरों पर रहकर गैस सिलेंडर की बुकिंग कर लें। उनके घर पर 72 घंटे के अंदर यानी तीन दिनों के अंदर गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा ।यह बार-बार अपील की जा रही है इसके बावजूद गैस एजेंसी के गोदाम या कार्यालय पर आकर अनावश्यक व्यवधान पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

एक नजर

कटे कनेक्शन के बाद भी चल रहा था आरओ प्लांट, बिजली चोरी में लाखों का जुर्माना

डुमरांव। बलिहार क्षेत्र में बिजली विभाग ने अवैध बिजली उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यावसायिक परिसर में संचालित आरओ प्लांट का भंडाफोड़ किया है। विभागीय टीम ने छापेमारी के दौरान पाया कि पूर्व में बकाया बिल के कारण काटे गए कनेक्शन के बावजूद उपभोक्ता चोरी की बिजली से प्लांट चला रहा था। सहायक विद्युत अभियंता अर्जुन वर्मा और कनीय अभियंता जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने ब्रजेश सिंह के परिसर में जांच की। निरीक्षण में सामने आया कि करीब 29,230 रुपये बकाया होने के कारण कनेक्शन पहले ही विच्छेदित कर दिया गया था। इसके बावजूद संचालक द्वारा एलटी लाइन से अवैध रूप से ह्यटोकाह्ल लगाकर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। मौके पर लगभग 4.810 किलोवाट का अवैध लोड भी पाया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस अवैध खपत से बिजली कंपनी को करीब 3,87,427 रुपये का नुकसान हुआ है। बकाया राशि को जोड़ते हुए कुल 4,16,657 रुपये का जुमार्ना संबंधित उपभोक्ता पर लगाया गया है। छापेमारी के दौरान उपभोक्ता के मौजूद रहने और मीटर जब्त करने में बाधा डालने की भी जानकारी सामने आई है। इस संबंध में विभाग द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्व नुकसान रोकने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और अन्य उपभोक्ताओं को भी सख्त संदेश गया है।

असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नियमावली का विरोध

आरा। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नई नियमावली को लेकर व्यापक विरोध शुरू हो गया है। इस नियमावली को लोकभवन द्वारा तैयार किया गया है, जिसके खिलाफ शिक्षक संगठनों और शैक्षणिक समुदाय में असंतोष देखा जा रहा है। खासतौर वीकेएसयू के अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ आदित्य कुमार आनन्द ने इसका कड़ा विरोध जताया है। विरोध के बाद अब यह मुद्दा राज्य स्तर पर भी तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने न केवल इस नियमावली को वापस लेने की मांग की है, बल्कि इसमें आवश्यक संशोधन करने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि वर्तमान नियमावली में कई ऐसी खामियां हैं जो योग्य अभ्यर्थियों के हितों के खिलाफ हैं। इस मामले में टीएमबीयू के सिंडिकेट सदस्य सह एएमयूसी के डॉ. संजीव कुमार सिंह ने भी संशोधन की मांग उठाई है। उन्होंने इस संबंध में कुलाधिपति, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पत्र में उन्होंने कहा है कि यूजीसी के नियमों की अनदेखी करते हुए राज्यस्तरीय परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया तय की गई है, जो कि उचित नहीं है।डॉ. सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इस नई नियमावली में नेट, जेआरएफ और पीएचडी जैसी योग्यताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और यूजीसी के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप बनाया जाए। कुल मिलाकर,यह विवाद अब शिक्षा जगत में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि पर जहां पर संघ के संरक्षक डॉ अमर कुमार ने कहा कि बिहार के मेधा का हनन हो रहा है और पूर्व से कार्य कर रहे अतिथि प्राध्यापकों को ही सेवा संयोजन करना चाहिए। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालय के अतिथि प्राध्यापकों ने कहा की हम चरणबद्ध आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। बैठक में डॉ राकेश चौधरी, डॉ अनंत कुमार, डॉ धनंजय प्रसाद राय, डॉ अमरेश कुमार, डॉ उमेश राय, डॉ. अशोक तिवारी, डॉ अनामिका कुमारी, डॉ संजय कुमार, डॉ श्वेता कुमारी, डॉ जुगल किशोर, डॉ कंचन कुमारी, डॉ अनुज कुमार, डॉ रत्नेश कुमार, डॉ राजेश सिंह, डॉ छाया कुमारी, डॉ मिथिलेश कुमार, डॉ मुकेश कुमार सहित सभी ने अपना- अपना विरोध दर्ज करवाया।

अनुमंडल मुख्यालय पीरो में उत्सवी माहौल में मनेगा बिहार दिवस

पीरो। अनुमंडल मुख्यालय में बिहार दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह उत्सव के रुप में आयोजित होगा। तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तरह की सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां आयोजित की जाएगी' इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अनुमंडल प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय की मौजूदगी में आयोजित एक बैठक के दौरान पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रुपरेखा तैयार की गई। इस दौरान तय किया गया कि 22 मार्च को स्थानीय शहीद भवन में तीन दिवसीय उत्सव का रंगारंग आगाज होगा। इस मौके पर छोटे-छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस दिन दोपहर में छात्र-छात्राओं व अभिभावकों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसमें अलग अलग इवेंट शामिल किए जाएंगे। जो 22 मार्च को संध्या पहर एक रैली निकाली जाएगी। जिसमें छात्र-छात्राओं के साथ-साथ अन्य लोग भी शामिल होंगे। 23 मार्च को सुबह शहीद भवन में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि दोपहर में स्थानीय पड़ाव मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगी। जिसमें बच्चे और अभिभावक भाग लेगें। 23 मार्च को संध्या पहर शहीद भवन में कवि सम्मेलन व मुशायरा का आयोजन होगा। इसी तरह 24 मार्च को अनुमंडल अंतर्गत पीरो,चरपोखरी व तरारी प्रखंड के स्कूली छात्र-छात्राओं के बीच क्वीज, गणित ओलम्पियाड, मेंहदी प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 24 मार्च को ही दोपहर में सम्मान समारोह व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पूरे कार्यक्रम की तैयारी के लिए बुधवार को आयोजित बैठक में बीइओ मनोज सिंह, उप समाहर्ता भूमि सुधार वरुणजय कुमार के अलावे कई निजी व सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मौजूद थे।

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मस्जिद-कब्रिस्तान विवाद सुलझा, आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे का रास्ता हुआ साफ

एजेंसी। पटना

बिहार के समस्तीपुर जिले से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर हाईवे निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब काफी हद तक सुलझ गया है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद हाईवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उदरअसल, पहले बिहार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने इन जमीनों पर निर्माण कार्य और अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। ट्रिब्यूनल का कहना था कि जिन जमीनों पर मस्जिद और कब्रिस्तान दर्ज हैं, उनका अधिग्रहण वक्फ अधिनियम 1995 के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। इस आदेश के चलते हाईवे प्रोजेक्ट का काम रुक गया था और आगे की प्रक्रिया बाधित हो गई थी।इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ठल्ठअक का कहना था कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 के तहत होती है, जो अपने आप में पूरी तरह सक्षम और स्वतंत्र कानून है। ऐसे में वक्फ ट्रिब्यूनल को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है।एमामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने स्पष्ट कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को जमीन अधिग्रहण या निर्माण कार्य पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसका आदेश कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक हित में जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 91 बाधा नहीं बन सकती। हालांकि, अदालत ने यह जरूर कहा कि वक्फ बोर्ड को इस प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है, ताकि उसे मुआवजे से संबंधित जानकारी दी जा सके और वह अपनी बात रख सके। इस फैसले के बाद लंबे समय से अटका हुआ आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ठल्ठअक ने समस्तीपुर जिले के शाहपुर और मोहिउद्दीनपुर इलाके में कुछ जमीनों का अधिग्रहण किया था, जिनमें मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन भी शामिल थी। इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और मामला वक्फ ट्रिब्यूनल तक पहुंचा था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट में आ रही बाधाएं दूर हो गई हैं और निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे होगा। यह लगभग 189 किलोमीटर लंबा होगा और आमस से शुरू होकर दरभंगा जिले में एनएच-27 तक जाएगा।

एक नजर

रसोई गैस की कालाबाजारी पर सरकार सख्त 293 सिलेंडर जब्त और 12 गिरफ्तार

पटना। बिहार में एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने व्यापक अभियान में 293 सिलेंडर जब्त किए और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले के फारबिसगंज में सबसे ज्यादा 261 सिलेंडर जब्त हुए। सभी जिलों में छापेमारी और जांच जारी है। राज्य में गैस सिलेंडर की कृत्रिम किल्लत दिखाकर कई स्थानों पर कुछ जमाखोर इसका फायदा उठाने की फिराक में लगे हैं। इसके मद्देनजर पुलिस महकमा के स्तर से सभी जिलों में व्यापक अभियान चलाकर ऐसे जमाखोरों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है। हाल में डीजीपी विनय कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को जांच के समुचित आदेश दिए थे। इसके बाद सभी जिलों में इसे लेकर जांच, छापेमारी और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी इस मामले की सतत मॉनीटरिंग चल रही है। विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों के दौरान एलपीजी के अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ के तहत चलाए गए व्यापक अभियान में 10 एफआईआर दर्ज करते हुए 293 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस दौरान कालाबाजारी में शामिल 12 व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न जिलों के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किए गए हैं। अररिया जिला के फारबिसगंज थाना में दर्ज मामले में सबसे ज्यादा 261 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा शिवहर जिला के शिवहर थाना क्षेत्र में 6 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 2 की गिरफ्तारी हुई है। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान थाना में 1 एलपीजी के साथ 1 आरोपी, बेगूसराय के लाखो थाना में 11 एलपीजी के साथ 1 आरोपी, सारण के हरिहरनाथ दो एफआईआर दर्ज की गई, एक में 3 सिलेंडर के साथ 1 आरोपी एवं दूसरे में 1 सिलेंडर के साथ 1 आरोपी, सारण के ही नगर थाना में 3 सिलेंडर के साथ 2 आरोपी, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में 7 एलपीजी सिलेंडर के साथ 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सिवान के मुफस्सिल और कटिहार जिले के सहायक थाना में गैस सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। सभी मामलों एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की जांच जारी है। अन्य जिलों में भी गैस की जमाखोरी को लेकर छापेमारी चल रही है।

तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूल वाहन और ऑटो को रौंदा : 13 घायल, आरा-पटना फोरलेन पर दहशत

आरा। भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। घटना आरा-पटना फोरलेन पर मनभावन होटल के समीप घटी, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले एक स्कूल वाहन को टक्कर मार दी और फिर पास में खड़े ऑटो को भी जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में स्कूल वाहन पर सवार छात्र-छात्राएं, शिक्षिकाएं और ऑटो में सवार पिता-पुत्र समेत कुल 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और अफरा-तफरी के बीच घायलों को तुरंत किसीलवर पीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों की स्थिति गंभीर देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जमुई में 6 हजार करोड़ की लागत से बनेगा स्टील प्लांट, सम्राट चौधरी ने किया ऐलान : कहा..नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी

एजेंसी। पटना

बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से समृद्धि यात्रा के दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमुई और नवादा के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। उन्होंने जमुई में 6 हजार करोड़ रुपये के स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना की जानकारी दी, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जमुई जिले में 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से स्टील प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही भीमबांध और कुंड घाट को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई और नवादा पहुंचे उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने जमुई के लछुआर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में बुनियादी सुविधाओं का गंभीर अभाव था। उस समय सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं। उन्होंने कहा कि तब राज्य में केवल 6 हजार किलोमीटर सड़कें थीं, जो अब बढ़कर 1 लाख 40 हजार किलोमीटर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट पहले लगभग 23 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का हो चुका है। बिजली के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, अब यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गई है। राज्य में 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे लगभग 88 प्रतिशत परिवारों का बिजली बिल पिछले सात महीने से शून्य आ रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। आज जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं राज्य की अर्थव्यवस्था में 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपये का योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें और पलायन पूरी तरह समाप्त हो सके। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 50 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार दिया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जमुई की पहचान पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में होती थी, लेकिन एनडीए सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त कर यहां विकास का माहौल बनाया है। अब जमुई पर्यटन के क्षेत्र में भी उभर रहा है। कुंड घाट जलाशय का उद्घाटन किया गया है और बरनार जलाशय को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टील प्लांट और इथेनॉल प्लांट स्थापित होने के बाद लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं नवादा के आईटीआई मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नवादा की पहचान भी कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में थी, लेकिन अब यहां शांति और विकास का माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है और आज बिहार की सड़कों की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि नवादा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंगा से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। फुलवरिया डैम को विकसित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे सस्ती बिजली और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा।

नीतीश कुमार फिर बनेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष! 19 मार्च को भरेंगे नामांकन, पार्टी में एकजुटता का बड़ा संदेश

एजेंसी। पटना

बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा संकेत सामने आया है, जहां नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। (जदयू) के भीतर इस फैसले को लेकर व्यापक सहमति दिखाई दे रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि जदयू का हर कार्यकर्ता और नेता चाहता है कि नीतीश कुमार ही दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें। उनके मुताबिक, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी को न केवल मजबूती मिली है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी एकजुटता बनी रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार ने नामांकन से जुड़े सभी जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि वे एक बार फिर इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके नामांकन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी साफ दिख रहा है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमर झा समेत करीब 10 वरिष्ठ नेता उनके प्रस्तावक बनाए गए हैं, जो उनके नेतृत्व पर पार्टी के भरोसे को दर्शाता है। जदयू द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 मार्च तय की गई है। यदि इस पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, तो 27 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। वहीं, यदि केवल एक ही उम्मीदवार का नामांकन होता है, तो नाम वापसी की अंतिम तिथि पर ही औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना जदयू के लिए रणनीतिक रूप से अहम होगा। बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ और अनुभव पार्टी को आगामी चुनावों में फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही, उनके नेतृत्व में जदयू अपने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में काम कर सकती है।राजनीति पार्टी के अंदरूनी हालात भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार के सामने किसी बड़े चुनौतीकर्ता के सामने आने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर, 19 मार्च को होने वाला नामांकन जदयू की राजनीति में एक अहम पड़ाव साबित होगा, जो यह संकेत देगा कि आने वाले समय में पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी और नीतीश कुमार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 6.44 लाख रुपये के जाली नोटों के साथ दो गिरफ्तार

एजेंसी। पटना

बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने एक बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई करते हुए जाली नोट छापने और उसकी सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का पदार्फाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुल 6,44,000 की नकली भारतीय करेंसी बरामद की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी सफलता है। यह पूरा मामला 15 मार्च 2026 की रात का है। करीब 8:10 बजे पुलिस को एक विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली कि मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति भारी मात्रा में नकली नोट लेकर पहुंचने वाला है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। नगर थाना पुलिस के सहयोग से रेलवे स्टेशन के दोनों निकास द्वारों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। आने-जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, ताकि संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत रोका जा सके। करीब 10:25 बजे एक युवक स्टेशन के गेट नंबर-02 की ओर आता दिखाई दिया। पुलिस की मौजूदगी देखकर वह घबरा गया और अचानक पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सूर्यदेव कुमार उर्फ सूरज कुमार बताया, जो नालंदा जिले का निवासी है। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में नकली भारतीय करेंसी नोट पाए गए। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि ये सभी नोट जाली हैं। उसने बताया कि वह ये नोट गया जिले के रहने वाले उदल पासवान से लेकर आया था। साथ ही उसने खुलासा किया कि इन नकली नोटों को नेपाल के एक व्यक्ति को सौंपने की योजना थी, जिससे इस गिरोह के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। सूर्यदेव कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने तुरंत गया जिले में छापेमारी की। इस दौरान दूसरे आरोपी उदल पासवान को गिरफ्तार किया गया। उसके घर की तलाशी के दौरान भी बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए। पूछताछ में उदल पासवान ने बताया कि वह बोधगया क्षेत्र में किराये के मकान में जाली नोट छापने का काम करता था।

सिलिंडर ब्लास्ट से ऊष्मामठ बाजार में हड़कंप, छह से ज्यादा लोग झुलसे, डीएमसीएच में पांच का इलाज जारी

एजेंसी। पटना

दरभंगा के ऊष्मामठ बाजार में सिलिंडर ब्लास्ट से छह से अधिक लोग झुलस गए। पांच गंभीर घायलों का डीएमसीच में इलाज जारी है, जबकि अन्य को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। दरभंगा के एपीएम थाना क्षेत्र स्थित ऊष्मामठ बाजार में सिलिंडर ब्लास्ट की घटना में छह से ज्यादा लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि पेथीयागाछी हाट में नाश्ते की दुकान पर जल रहे चूल्हे का सिलिंडर अचानक ब्लास्ट हो गया। विस्फोट की चपेट में कई लोग आ गए, जिससे बाजार में अफरातफरी का माहौल बन गया। घटना में गंभीर रूप से जले पांच लोगों को डीएमसीच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों को अस्पताल लेकर आए राजू कुमार ने बताया कि उनकी मां डोमनी देवी, पतोर थाना क्षेत्र की हीरा देवी और उनकी बेटी मेनका कुमारी, साथ ही पेथीयागाछी निवासी लालू साह और उनके बेटे चंदन साह को डीएमसीच में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कई अन्य घायलों को आसपास के निजी क्लिनिक में भी भर्ती कराया गया है। एक साथ इतने मरीजों के पहुंचने से अस्पताल में भी अफरातफरी का माहौल देखा गया, वहीं परिजन भी बड़ी संख्या में वहां जुटने लगे। बाजार में मौजूद कमल कुमार शर्मा ने बताया कि ऊष्मामठ के पेथीयागाछी साप्ताहिक हाट में कचरी-मुरही बेचने वाले का सिलिंडर अचानक ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद कई लोग घायल होकर बाजार में ही गिर पड़े। यह दृश्य देखकर लोगों के बीच हड़-कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक ही एम्बुलेंस में पांच गंभीर रूप से जले लोगों को डीएमसीच भेजा। अपनी मां का इलाज कराने पहुंचे राजू कुमार साह ने बताया कि उनकी मां डोमनी देवी सब्जी खरीदने के लिए पेठियागाछी हाट आई थीं। इसी दौरान कचरी बनाने वाले का सिलिंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से जल गईं। उन्होंने बताया कि बाजार में मौजूद लोगों से घटना की जानकारी मिलने के बाद वे डीएमसीच पहुंचे, जहां उनकी मां समेत पांच लोगों का इलाज चल रहा है।

बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी : मॉडल स्कूलों के लिए ट्रांसफर शुरू, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

एजेंसी। पटना

बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार अब उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मॉडल स्कूल विकसित करने जा रही है, जिसके तहत विषयवार रिक्तियों के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर और पदस्थापन किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। शिक्षा विभाग के इस निर्णय के अनुसार, प्रत्येक प्रखंड में एक-एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन स्कूलों को आधुनिक संसाधनों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित शिक्षकों से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर को कम किया जा सके। इसके लिए विभाग ने पहले से कार्ययोजना तैयार कर ली है और तेजी से क्रियान्वयन शुरू किया जा रहा है।

ई-शिक्षा कोष पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया शुरूः जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इस पोर्टल को खोला गया है। जिले के विभिन्न हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अपनी योग्यता और विषय के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षकों को अपनी प्राथमिकताएं भी देने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें मनपसंद स्थान पर पदस्थापन की संभावना बढ़ेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

नए सत्र से शुरू होगी पढ़ाईः सरकार का लक्ष्य है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से ही इन मॉडल स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दी जाए। इसके लिए पहले चरण में सभी आवश्यक विषयों के शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। विभाग इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि किसी भी विषय में शिक्षक की कमी न रह जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मॉडल स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को भी शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों को नई तकनीक के साथ सीखने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी।

रिक्त पदों के आधार पर होगा ट्रांसफरः शिक्षकों का ट्रांसफर पूरी तरह से विषयवार रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। जिस स्कूल में जिस विषय के शिक्षक की आवश्यकता होगी, उसी के अनुसार पदस्थापन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर विषय के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हों। इसके अलावा, शिक्षकों द्वारा आवेदन में दिए गए विकल्पों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यानी शिक्षक जिस स्थान या स्कूल को प्राथमिकता देंगे, विभाग उसी के अनुसार उन्हें पदस्थापित करने का प्रयास करेगा। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक संतुलित और न्यायसंगत बनेगी।

विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधानः मॉडल स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को विभाग की ओर से विशेष आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करना और उन्हें बेहतर संसाधनों के साथ पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे।

जेडीयू ने 2 नेताओं की सदस्यता रद्द की, 3 साल के लिए पार्टी से निकाला

एजेंसी। पटना

दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अगले तीन साल के लिए निष्कासित किया गया है और जेडीयू कार्यालय में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। जनता दल यूनाईटेड (जेडीयू) ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीयू के दो नेताओं की प्राथमिक सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। दोनों को अगले तीन साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के चलते यह कार्रवाई की गयी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिन दो नेताओं पर कार्रवाई की गयी है। उनमें

से एक पटना के रुपसपुर निवासी अभय पटेल हैं और दूसरा पटना के राम कृष्णा नगर के रहने वाले एस.के.सुमन हैं। जिनकी सदस्यता खत्म कर दी गयी है। दोनों को 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। दोनों के जेडीयू कार्यालय में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गयी है।